in different sectors, there was improvement in the growth-rate of the economy, buoyancy in public revenues and decline in the rate of inflation.

बंजर भूमि क्षेत्र

2221. **डा० रत्नाकर पांडेय** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश मे ऐसी कुल कितनी बंजर भूमि है, जिसका खेती के लिए और वन रोपण के लिए उपयोग नही किया जा सकता ;

(ख) उसमें से कितनी भूमि में वन लगाये जाने का विचार है ,

(ग) वन रोपण की सम्पूर्ण योजना को कितने चरणो में पूरा किया जायेगा ; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की कुल कितनी बजर भमि का उपयोग किए जाने की सभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी) : (क) राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वार किए गए एक आकलन के अनुसार देश मे गैर-वन और अवक्रमित वन क्षेत्र लगभग 175 मिलियन हेक्टेयर है ।

(ख) और (ग) अगले कुछ वर्षों मे कुल वनरोपण कार्यक्रम निम्नानुसार होने की उम्मीद है :—

वर्ष	मिलियन हेक्टेयर
1986–87 . .	1.7
1987–88 . .	2.3
1988–89 . .	3 0
1989–90 . .	4.0
1990–91 . .	5.0

(घ) वन रोपण के लिए परती भूमि का निर्धारण साल-दर साल आधार पर किया जाता है ।

हिन्दी समाचार समितियों का बन्द किया जाना

2222. **डा० र लाकर पांडेय** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी की दोनो समाचार समितियां हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती या तो बद कर दी गयी है अथवा बद प्राय हो गयी है ,

(ख) क्या अहिन्दी राज्यो मे काम कर रही इन समितियो ने राजभाषा विभाग से कोई सहायता मागी थी ,

(ग) यदि हा, तो इस मामले मे क्या निर्णय लिया गया , और

(घ) क्या सरकार ऐसी किसी सस्था को सहायता प्रदान करेगी, जो हिन्दी अथवा अन्य किन्ही भारतीय भाषाओ मे समाचार वितरित करेगी ?

सूचना और प्रसारण मत्रालय के राज्य मत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) देश मे समाचार एजेंसिया निजी स्वामित्व मे है और सरकार प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप इनके आन्तरिक कार्य सचालन मे हस्तक्षेप नही करती । इसलिए सरकार को इस बात की जानकारी नही है कि क्या हिन्दी की प्रश्नास्पद दो समाचार एजन्सियां वास्तव मे कार्य कर रही है । तथापि, समाचार पत्र उद्योग मे यह व्यापक धारणा है कि ये दोनो एजेंसियां, अपनी बिगडी आर्थिक स्थिति के कारण, वास्तव मे ठप हो गई है ।

(ख) और (ग) राजभाषा विभाग को हिन्दुस्तान समाचार से आर्थिक सहायता के लिए एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था । इसे स्वीकार नही किया जा सका, क्योकि इस विभाग की इस प्रकार की सहायता देने की कोई स्कीम नही है ।

(घ) जी, नही ।